poses to observe one day all India Token strike in the 3rd week of August, 1991. The employees of Regional Rural Banks have already been allowed pay scales etc. applicable to equated posts in sponsor banks w.e.f. 1.1.91. A working group created by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) will consider the matters relating to promotion policy in Regional Rural Banks, framing of service regulations and also for considering any other matters affecting RRB employees.

Cash allowance to cashiers of RRBs sponsored by SBI

1329. SHRI ASHIS SEN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Regional Rural Banks sponsored by State Bank of India in Andhra Pradesh are being allowing cash allowance to the cashiers as per Rules in State Bank of India and such banks sponsored by the SBI in other States are not being allowed the same; and

(b) if so, what are the reasons for such discrimination?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Environmental risks in pesticide use

1330. SHRI SHAMIM HASHMI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the Government have examined the various environmental risks in pesticide use; and

(b) whether a parliamentary fact-finding committee is proposed to be set up to look into the matter?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Government are aware of the environmental risks due to the use of pesticides some of which are contamination of water, soil and food, bio-accumulation and environmental persistence. The Registration Committee constituted under the Insecticides Act, 1968 carefully evaluates environmental risks of pesticides before recommending them for registration for manufacture and use. Pesticides already registered are screened by expert committees and regulatory action taken accordingly.

(b) There is no proposal under consideration of the Government.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में निदेशकों के रिक्त पद

1331. **डा० अबरार अहमद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जहां इस समय निदेशकों के पद खाली पड़े हैं; ये पद कब से खाली पड़े हैं तथा इनका श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और इन रिक्त पदों के कब तक भर लिए जाने की संभावना है;

(ख) सरकार द्वारा निदेशकों के नाम निर्देशन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान कितने निदेशक नियुक्त किये गये?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) संभवतः इस प्रश्न का आशय 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों की रिक्तियों से संबंधित सूचना प्राप्त करना है। 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में सितम्बर से अक्टूबर, 1989 के दौरान 102 गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्तियां की गयी थीं। इस समय 99 गैर-

सरकारी निदेशक कार्यरत हैं। फिलहाल 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में 81 रिक्तियां हैं, जिनमें से अधिकांश 1985 में खाली हुई थीं। रिक्तियों की श्रेणी-वार स्थिति इस प्रकार है:-

जमाकर्ता . . .	5
कृषक . . .	8
कारीगर . . .	11
कार्मिकों की सामान्य श्रेणी .	20
अन्य . . .	37

गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्तियां राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजनाएं, 1970 तथा 1980 में दी गयी पद्धति तथा मान-दण्डों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। उक्त योजना में, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात् इन निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान है।

20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों की रिक्तियां भरने के लिए सरकार ने पहले ही आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

खर्च कर दी गई विदेशी प्रतिभूतियां

1332. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मार्च, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फारेन सिक्यूरिटीज इनजास्टेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उस विदेशी प्रतिभूति निधि को भी खर्च कर दिया गया जिसे बहुत असाधारण और विशेष स्थितियों से निपटने के लिए आरक्षित रखा गया था;

(ग) यदि हां, तो इस निधि को कब खर्च किया गया; और

(घ) इसके बदले में आयात की गई वस्तुओं का मूल्य और मात्रा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। बहुत असाधारण और विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए कोई विदेशी प्रतिभूति निधि आरक्षित नहीं रखी जाती। विदेशी प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों का एक हिस्सा है। इन प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री आरक्षित प्रबंध के एक हिस्से के रूप में सतत् आधार पर की जाती है।

(ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(घ) विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री संबंधी लेन-देन किसी तरह के निर्यात के बदले में नहीं किया जाता।

Issue of identity cards to voters

1333. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to issue identity cards to voters with a view to reducing malpractices during elections; and

(b) if so, by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. R. KUMARAMANGALAM): (a) Yes, Sir.

(b) Taking into account the huge number of voters, expenditure and the administrative steps involved in the operation, the introduction of